## AIDCF MOVES TDSAT AGAINST DD FREE DISH

DD Free Dish has been under fire from AIDCF – the All India Digital Cable Federation) which has moved

the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) against DD Free Dish for allegedly not abiding by TRAI's regulation that requires the channels to be provided in an encrypted manner.

"TRAI has defined the category of channels as Pay Channel or FTA (i.e., Free to Air) channels as per its regulations and all the broadcasters define their channels as Pay or FTA. However, some channels, which are declared as pay channels by broadcasters are available as free-to-air (FTA) on DD Free Dish platform which is resulting a non-level-playing field between DD free Dish and MSOs," said Peeush Mahajan, President, AIDCF.

The petition, filed by AIDCF and GTPL Hathway Ltd, which sought compliance with the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 applicable to Broadcasting Services in India and in particular that the Prasar Bharati provides all private television channels through encrypted signal for DD Free Dish Service.

The plea has alleged that broadcasters have been providing TV channel decoders of certain pay channels to the DTH platform DD Free Dish, without charging any tariff for the pay channels.

It also sought that all agreements between Prasar Bharati and private broadcasters, which are contrary to TRAI regulations, be declared null and void.

The cable federation urged the tribunal to ensure that all private television channels are broadcast to the end consumer in encrypted form through digital addressable systems.

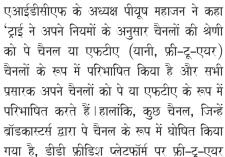
48

## एआईडीसीएफ ने डीडी फ्री डिश के खिलाफ टीडीसैट का रूख किया

डीडी फ्री डिश, एआईडीसीएफ-(ऑल इंडिया डिजिटल केबल

फेडरेशन) के निशाने पर है, जिसने कथित तौर पर ट्राई के नियमों का पालन नहीं करने के लिए डीडी फ्री डिश के खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) का रूख किया है, जिसके लिए चैनलों को एन्किप्टेड तरीके से उपलब्ध कराने

की आवश्यकता है।



(एफटीए) के रूप में उपलब्ध है, जिसके परिणामस्वरूप डीडी फ्री डिश और एमएसओ के वीच एक स्थितियां विल्कृल अलग-अलग है।

एआईडीसीएफ और जीटीपीएल हेथवे लिमिटेड द्वारा दायर याचिका, जिसमें भारत में प्रसारण सेवाओं पर लागू दूरसंचार (प्रसारण और केवल) सेवा मानको और सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेवल सिस्टम) विनियम, 2017 के अनुपालन की मांग की और विशेष रूप से प्रसार भारती सभी निजी टेलीविजन चैनलों को डीडी फ्रीडिश सेवा के लिए एन्किप्टेड सिगनल के माध्यम से प्रदान करता है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रसारक पे चैनलों के लिए कोई टैरिफ चार्ज किये बिना, डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश को कुछ पे चैनलों के टीवी चैनल डिकोडर प्रदान कर रहे हैं।

इसमें यह भी मांग की गयी है कि प्रसार भारती और निजी प्रसारकों के बीच सभी समझौते, जो ट्राई नियमों के विपरित है, को अमान्य घोषित किया जाए।

केवल फेडरेशन ने ट्रिट्यूनल से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी निजी टेलीविजन चैनल डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से एन्किप्टेड रूप में अंतिम उपभोक्ता तक प्रसारित किये जायें। ■





SATELLITE & CABLE TV OCTOBER 2023